Shodh International: A Multidisciplinary International Journal (In Hindi)
Vol. 6, Issue 2 – 2021
ISSN: 2581-3501

भारत बनाम चीन-पाक कूटनीतिक गठजोड़: जम्मू-कश्मीर राज्य के विशेष संदर्भ में

डॉ. नर्वदेश्वर पाण्डेय[1], कोमल[2]

[1]सह-आचार्य, रक्षा एवं स्त्रातजीय अध्ययन, का.सु.साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अयोध्या।

[2]अनुसंधित्सु-रक्षा एवं स्त्रातजीय अध्ययन, का.सु. साकेत स्नातकोतर महाविद्यालय अयोध्या।

(डॉ राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से संबद्ध)

सारांश

भारत व पाकिस्तान दक्षिण एशिया के ऐसे दो निकटतम पड़ोसी हैं जिनके मध्य विभाजन काल से ही जम्मू कश्मीर को लेकर विवाद की स्थिति सदैव बनी रही है, परंतु इस विवाद में पाकिस्तान द्वारा चीन को प्रवेश दिलाकर आग में घी डालने वाला काम किया है। पाकिस्तान की इन्ही कारगुजारियों के चलते कश्मीर विवाद को शायद विश्व इतिहास के सबसे लम्बे चलने वाले विवाद में शुमार कर दिया। गौरतलब है कि कश्मीर के महाराजा हरि सिंह के द्वारा जम्मू कश्मीर को भारत के पक्ष में हस्तगत करने के उपरांत भारत ने अपना पक्ष मजबूत बनाये रखा है। पाकिस्तान द्वारा प्रदत्त कश्मीर की लगभग 20 प्रतिशत भूमि चीन के कब्जे में है, जिसपर चीन ने अपनी महत्वकांक्षी परियोजना चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) का निर्माण कर लिया है, जो कि भारतीय भू-प्रदेश पर एक प्रकार अतिक्रमण है। इसी गलियारे के द्वारा पाकिस्तान को भारत विरोधी लगभग 46 बिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता निरंतर दी जा रही है, और निकट भविष्य में इसी रास्ते से पाक को सैन्य सहायता भी दी जा सकती है, जो भारतीय के लिए रणनीतिक तौर पर घातक सिद्ध होगा। इन्हीं होगा। इन्हीं वजहों से पाकिस्तान द्वारा चली गयी इस कूटनीतिक चाल को भारत द्वारा विफल करने के भरसक प्रयास जारी है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में लागू आर्टिकल 370 जो कि राज्य को विशेष राज्य का दर्जा

© Eureka Journals 2021. All Rights Reserved.

प्रदान करता है, को भारतीय संसद द्वारा स्थायी रूप से निरस्त कर देने से पाकिस्तान और चीन दोनों सशंकित नज़र आते हैं। कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त होने के एक साल बीतने उपरांत 5 अगस्त को चीन ने अपने सहयोगी पाकिस्तान का पक्ष लेते हुए इस मुद्दे को फिर से उछाला है। चीन ने कश्मीर से धारा 370 हटाने के एक साल बाद प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि "भारत का यह कदम अवैध और अमान्य है"। आगे चीन ने यह भी कहा कि कश्मीर की यथास्थिति से छेड़छाड़ उसे स्वीकार नहीं है। इस पर भारत ने चीन की टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रलाय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने, जम्मू-कश्मीर पर भारत सरकार सरकार इस फैसले के एक साल पूरा होने के मौके पर चीन की टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि "हमने भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की टिप्पणियों पर गौर किया है। चीनी पक्ष का इस विषय पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है और उसे अन्य राष्ट्रों के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी नहीं करने की सलाह दी जाती है।" इधर आरम्भ से जम्मू कश्मीर पर आँख गड़ाए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि अगर भारत जम्मू कश्मीर में अगस्त 2019 से पहले की स्थिति बहाल करता है, तो पाकिस्तान बातचीत के लिए तैयार है" पाकिस्तान और चीन की इस बौखलाहट को देखते हुए स्पष्ट रूप से समझ आता है पाक और चीन को जम्मू कश्मीर में अपने-अपने हित नज़र आते हैं।[1] जम्मू कश्मीर को लेकर हो रही चीन पाक गठजोड़ को देखते हुए भारत को सदैव सावधान रहना होगा।

शब्दकोश: कारगुजारियों, CPEC कठजोड़, गलियारे, UNSC कम्युनिस्ट, धारा 370.

प्रस्तावना

पाकिस्तान के साथ चीन का संबंध हमेशा से ही मधुर रहे हैं, और द्विपक्षीय रिश्तों की सामरिक शुरुआत 1950 के उत्तरार्द्ध में ही पड़ गई थी, जब चीन और भारत के संबंध में प्रतिकूल प्रभाव

© Eureka Journals 2021. All Rights Reserved.

Shodh International: A Multidisciplinary International Journal (In Hindi)
Vol. 6, Issue 2 – 2021
ISSN: 2581-3501

दिखाई देने लगे थे। भारत से प्रतिकूल रिश्तों के कारण पाकिस्तान की भौगोलिक स्थिति को चीन के लिए एक मूल्यवान दीर्घकालिक निवेश माना गया। भारत-चीन संबंधों में अस्थिरता की स्थिति के कारण अक्टूबर 1962 में युद्ध किया गया। कई वर्ष पहले पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफने चीन और पाकिस्तान की दोस्ती के अद्भुत कसीदे पढ़े थे.. चीन के ग्रेट हाल आफ द पीपुल में राष्ट्रपति ली केछियांग के कार्यक्रम में सामिल होते हुए नवाज शरीफ ने कहा था कि'' चीन और पाकिस्तान की दोस्ती हिमालय से ऊंची है, ये रिश्ता सबसे गहरे समंदर से ज्यादा गहरा और शहद से मीठा है। चीन हमारा सदाबहार मित्र है।'' पाकिस्तान और चीन का आपसी संबंध उतना ही पुरान है जितना पाकिस्तान का इतिहास। ताइपाई में चीनी गणतंत्र की सरकार से रिश्ता तोड़ कर पाकिस्तान के इस्लामिक गणतंत्र ने कम्युनिस्ट पार्टी को सबसे पहले मान्यता दी थी।

पाक चीन कठजोड़

चीन पाक गठजोड़ से भारत पर पड़ने वाले प्रभाव में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दा जम्मू कश्मीर राज्य से गुजरने वाले चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर (CPEC) मुख्य है। जिससे पाकिस्तान अपनी अर्थव्यश्वस्था सुधारने की उम्मीद लगाए बैठा है। उसे उम्मीद है कि (CPEC) से चीन और पाकिस्तान दोनों का फायदा होगा। चीन के नजरिए से देखें तो शी जिनपिंग के वन बेल्ट वन रोड का प्रमुख हिस्सा है। जिससे चीन के लिए अरब महासागर तक का रास्ता खुल जाएगा, और साथ ही खनिजों से परिपूर्ण प्रान्त बलूचिस्तान और ग्वादर बंदरगाह भी और पाकिस्तान के पक्ष में ये होगा कि चीन का निवेश उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा, पुराने पड़ते ढांचे को नया करेगा, ऊर्जा से जुड़े क्षेत्रों को मजबूत करेगा।

चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) चीन का एक मेगा प्रोजेक्ट है। इसका मकसद दक्षिण-पचिमी पाकिस्तान से चीन के उत्तर-पश्चिमी स्वायत्त क्षेत्र शिनजियांग तक ग्वादर बंदरगाह, रेलवे और हाइवे के माध्यम से तेल और गैस की कम समय में सप्लाई करना है। कॉरिडोर ग्वादर से काशगर तक लगभग 2442 किमी लंबा है। यह कॉरिडोर POK गिलगित-बाल्टिस्तान और बलूचिस्तान से होकर गुजरेगा। इस प्रोजेक्ट की योजना 1950 के दशक में हुई थी, परंतु पाकिस्तान में व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता के चलते यह प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में रहा। चीन ने साल 1998 के में पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह पर निर्माण कार्य शुरु किया था, जो

© Eureka Journals 2021. All Rights Reserved.

2002 में पूरा हुआ थी। चीन के शी जिनपिंग की सरकार ने 2014 में CPEC की आधिकारिक रूप से घोषणा की थी।

भारत सरकार इस योजना को जम्मू कश्मीर राज्य में अपनी संप्रभुता को दी गयी चुनौती मानता है और दृढ़ता के साथ इसका विरोध करता रहा है। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा संसद में पेश की गई अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि, 'POK से होकर गुजरने वाली परियोजना भारत की संप्रभुता के लिए एक चुनौती है।' यह कोई पहली बार नही था जब भारत की ओर से इस परियोजना का विरोध किया गया है।

यह आर्थिक गलियारा चीन के मुस्लिम-बहुल शिनजांग प्रांत को बलूचिस्तान स्थित ग्वादर बंदरगाह से परस्पर जोड़ता है। वर्तमान में यह कॉरिडोर चवा के गिल्गित- बाल्टिस्तान से होकर गुजरता है। भारत इस क्षेत्र को अपना संप्रभु हिस्सा मानता है। यही वजह है कि भारत इस परियोजना का विरोध कर रहा है।

G.20 शिखर सम्मेलन में भी भारत ने यह मुद्दा प्रमुखता से उठाया पिछले साल सितेबर में आयोजित हुए जी. 20 सम्मेलन के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ हुए द्विपक्षीय वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी CPEC को लेकर आपत्ति जताई थी।[2] भारत कमी ओर से यह स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि चीन का भी उसके सामरिक हितों के बारे में संवेदनशीलता बरतनी चाहिए। चीन द्वारा हाल ही में अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने के लिए पीपल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) को पुनर्गठित किए जाने का फैसला किया गया था इन खबरों पर संज्ञान लेते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने इंटरनैशलन वॉटर्स में आवाजाही मे आवाजाही और अंतरराष्ट्रीय समुद्रीय सीमा में आसमान के रास्ते विमानों के आने-जाने को समर्थन देने की अपनी प्रतिबध्दता दोहराई है।[3]

धारा 370 और चीन-पाक कूटनीत

भारत द्वारा कश्मीर की विशेष स्वायत्तता के समाप्त करने की घोषणा के ठीक एक दिन बाद, चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चुनयिंग ने अपने एक बयान में कहा "चीन हमेशा भारत द्वारा चीन के प्रशासनिक क्षेत्र को भारत के पश्चिमी क्षेत्र में चीनी क्षेत्र को शामिल करने का विरोध करता है।" आगे उन्होंने काहा कि "भारत अपने घरेलू कानून को बदलकर चीन की क्षेत्रीय संप्रभुता को लगातार नुकसान पहुंचा राह है। ऐसा परिवर्तन अस्वीकार्य है और लागू नहीं होगा।

© Eureka Journals 2021. All Rights Reserved.

Shodh International: A Multidisciplinary International Journal (In Hindi)
Vol. 6, Issue 2 – 2021
ISSN: 2581-3501

‘‘एक अलग बयान में चीनी विदेश मंत्रालय ने कश्मीरी में सामान्य क्षेत्रीय स्थिति के बारे में चिंता व्यक्त की। हुआ ने कहा,‘‘चीन जम्मू कश्मीर में मौजूदा स्थ्ति को लेकर अत्याधिक गंभीर है।[5]‘‘

चीन के इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि ‘‘जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विशेयक 2019, 5 अगस्त का संसद में सरकार द्वारा पेश किया गया, जा एक नए ‘‘केन्द्र शाशित प्रदेश लद्दाख’’ के गठन का प्रस्ताव है यह भारत के क्षेत्राधिकार से संबंधित आंतरिक मामला है। भारत अन्य देशों के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी नहीं करता है, और अन्य देशों से उम्मीद करता है कि वह ऐसे टिप्पणी नहीं करेंगे।[6]

इस प्रतिक्रिया के बाद अपने सर्वकालिक मित्र पाकिस्तान को खुश करने के लिए चीन ने अनुच्छेद 370 के मामले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उठा राह है इस बैठक में परिषद के सदस्यों के बीच बंद कमरे मे जम्मू -कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के मुद्दे पर बैठक होगी। ऱक्षा विशषज्ञों का कहना है कि चीन-पाकिस्तान को इस कदम से कुछ खास लाभ हासिल नहीं हाने वाला है। ऱक्षा विशेषज्ञों का मनना है कि अगर इस बैठक में भारत के खिलाफ कुछ प्रस्ताव आता भी है तो सुरक्षा परिषद के सदस्य इसके खिलाफ वीटो कर सकते है।[7]

संयुक्त राष्ट्र के एक सीनियर डिप्लोमैट ने बताया कि बैठया कि बैठक में सदस्यों के बीच क्लोज्ड-डोर कंसल्टेशन होगा, हालांकि इसमें पाकिस्तान का कोई भी सदस्य शामिल नहीं होगा, इस बैठक से जुड़े डिटेल्स का भी प्रसारण नही्र किया जाएगा, यानी कि इसमें पत्रकार भी मौजूद नहीं रहेंगे। चीन और पाकिस्तान इस बात पर थोड़ी देर के लिए भले ही प्रसन्न हो सकते है कि UNSC ने उनकी बात स्वीकार कर ली है। लेकिन यह कार्यवाही बेनतीजा ही साबित होगी। ऱक्षा विशेषज्ञ कमर आगा कहते हैं कि सुरक्षा परिषद के अधिकतर सदस्य ये मानते हैं कि कश्मीर का मुद्दा भारत-पाकिस्तान का द्विपक्षीय मुद्दा है और इसे दोनों को ही शान्ति से सुलझाना चाहिए। कमर आगा ने कहा, ’’ये तो संभव है। कि मीटिंग हो सकती है, उसकी एक प्रक्रिया होती है और UNSC के सदस्य साथ बैठ सकते हैं, अब इनकी कोशिश ये होगी कि भारत के खिलाफ प्रस्ताव पास करवाया जाए ये ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योकि अगर ऐसा कुछ होता हैं तो बहुत से देश उसके वीटो कर देंगे, एक नहीं बल्कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कई दंश वीटो कर देंगे -इसलिए कि सुऱक्षा परिषद के सभी सदस्यांका 370 पर जो बयान आयाहै उसमें सबने एक ही बात कही है कि ये दो प़क्षीय मामला है, ये भारत -पाकका आंतरिक मसला है।[8] और यही आपस

© Eureka Journals 2021. All Rights Reserved.

Shodh International: A Multidisciplinary International Journal (In Hindi)
Vol. 6, Issue 2 – 2021
ISSN: 2581-3501

में शांति वार्ता करें" पूर्व राजनयिक रहे स्कंद तयाल कर कहना है कि जम्मू -कश्मीर का मामला 1948 से संयुक्त राष्ट्र के पास है।[9] अब तक कुल मिलाकर इस पर सुरक्षा परिषद की ओर से 11 प्रस्ताव हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद जब इस मामले पर विचार करेगी तो इसी दिशा में निर्देश देगी कि जम्मू-कश्मीर का मामला भारत -पाकिस्तान के बीच का द्वविपक्षीय मामला है, हाल ही में रूस ने भी ऐसा बयान दिया है।

हालांकि प्रारंभिक तौर पर सुरक्षा परिषद में कूटनीति का दबाव भले ही भारत के पक्ष में दिख रहा हो परंतु चीन की इस चाल ने भारत को एक बार पुनः अपने पड़ोसी का लेकर सचेत कर दिया है।

UNSC के अध्यक्ष जोआना रेकोनाका ने भी पाक शिकायत पर कोई बयान देने से इन्कार कर दिया। इस प्रकार, पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विशेष सत्र बुलाने और भारतकी कार्रवाई के खिलाफ कोई भी प्रस्ताव पारित करने में विफल रहा।[10] हालांकि चीन के सहयोग से, 15 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा की एक अनौपचारिक बैठक 16 अगस्त को आयोजित की गई, जिसका कोई भी परिणाम नहीं निकल सका। बहुत से सदस्यों ने अनौपचारिकने अनौपचारिक विचार-विमर्श का हिस्सा बनने के पाकिस्तान के अनुरोध को ठुकरा दिया।[11] पाकिस्तान और चीन द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद केएक प्रस्ताव के माध्यम से या कम से कम एक सार्वजनिक बयान के माध्यम से भारत का रोकने का प्रयास भारी पड गया क्योंकि बहुमत ने इस तरह के किसी भी फैसले का विरोध किया। नई दिल्ली के इस विवाद के समर्थन में परिषद के अधिकांश गैर -स्थायी सदस्योके साथ-साथ फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका के विचार-विमर्श में देखा गया है कि जम्मू कश्मीर पर उसके फैसले भारत के आंतरिक मामले थे आंततिक मामले थे जिनका पाकिस्तान या चीन के साथ सीमा विवाद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।[12]

मुल्यांकन

भारत द्वारा कश्मीर में धारा 370 को समाप्त किए जाने के बाद, चीन पिछले साल अगस्त से ही पाकिस्तान के इशारे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर के मुद्दे को उठाने कि कोशिश कर रहा है, लेकिन अन्य वैश्विक शक्तियों द्वारा उसे बार-बार हताशा ही हाथ लगी है, फिर भी चीन ने अपनी कोशिशें नहीं कोशिशे नहीं छोड़ी हैं, क्यों कि वह इस्लामाबाद को यह दिखाना चाहता है किवह पाकिस्तानके साथ अपने सबंधों को लेकर कितना गंभीर और द

© Eureka Journals 2021. All Rights Reserved.

वचनबध्द अपने एक संयुक्त बयान मे चीन ने एक बार फिर से यह रेखांकित किया कि पाकिस्तान इस क्षेत्र में उसका कट्टर साझेदार है और वह पाकिस्तान ही क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता, स्वतंत्रता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए, उसका दृढता से समर्थन ‘‘करेगा साथ ही चीन’’ बाहरी सुरक्षा वातावरण बनाए रखने के लिए भी हर संभव कोशिश करेगा।[13]

चीन पर पाकिस्तान की लगातार निर्भरता बढ़ती जा रही, और दुनिया भर के अन्य प्रमुख साझेदारी के साथ अलगाव के बीच जल्द की बीजिंग का पाकिस्तान पर पूरी तरह नियंत्रित हो आने की संभावना है। अब पाकिस्तान को यह तय करना है कि क्या वह चीन के महिमामंडित उपनिवेश के रूप में अपनी पहचान से संतुष्ट है? जैसे दुनिया बदल रही है, पाकिस्तान के भारत के विरुध्द जुनून और और बदले की नीति का मतलब है कि उसकी विदेश नीति जमीनी हकीकत से नहीं बल्कि नई दिल्ली के प्रति उसके वैचारिक प्रतिशोध से संचालित होगी। समय ‘परिवर्तनशील है। और लगातार बदल रहा है, लेकिन पाकिस्तान समय की अपनी अलग परिभाषा गढ़ कर खुद ही उसमें फंसता चला जा रहा है।

संदर्भ सूची

1. https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/hindi/international-49327336.amp.
2. https://www.google.com/amp/s/www.livehindustan.com/international/story-china-gave-this-statement-after-the-request-of-pak-foreign-minister-to-beijing-on-370-2680278.amp.html.
3. https://www.google.com/amp/s/www.aajtak.in/amp/world/story/pakistan-would-hold-talks-with-india-if-new-delhi-restores-kashmir-pre-august-2019-status-says-pm-imran-khan-1263884-2021-05-31.
4. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.orfonline.org/hindi/research/article-370-ushering-in-the-new-normal/&ved=2ahUKEwjyyev0_ KH1AhU5T2wGHZ1qBeEQFnoECA4QAQ&usg=AOvVaw0lwwA8x_H3u6n-dg9DxnTr.
5. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.orfonline.org/hindi/research/pakistan-life-after-articles-370-and-35a/&ved=2ahUKEwjyye

© Eureka Journals 2021. All Rights Reserved.

v0_KH1AhU5T2wGHZ1qBeEQFnoECBIQAQ&usg=AOvVaw18wqTvWzxCQHUq5ZRUn9U2.

6. Ankit Panda, "China Issues Statement Condemning Indian Decision to Bifurcate Kashmir" at https://thediplomat.com/2019/08/china-issues-statement ondemning-indian-decision-to-bifurcate-kashmir/.
7. Prabhas K.Dutta, "Kashmir: Pakistan tries to isolate India over Article 370, gets a reality check", at https://www.indiatoday.in/news-analysis/story/kashmir-pakistan-tries-to-isolate-india-overParticle-370-gets-a-reality-check-1579988-2019 08-12.
8. Stop terror to start talks: India to Pakistan after UNSC meeting on Kashmir" at //economictimes.indiatimes.com/articleshow/70706523.cms? utm_source-contentofinterest & utm medium-text & utm_campaign = cppst"
9. World does not believe Pak, but India on Kashmir issue, says Pak minister", Business Standard, September 13, 2019.
10. Sreemoy Talukdar, "Chennai summit: Narendra Modi and Xi Jinping avoid Kashmir, discuss trade deficit and hit right notes but it's tricky to trust Beijing" at https://www.firstpost.com/india/chennai-summit-narendra-modi-and-xi-avoidjinping-kashmir-discuss-tradedeficit-summit-and-hitright-notes-but-its-tricky-to-trust-beijing7490581.html.
11. "Anti-China protests in Sindh to oppose economic corridor", Hindustan Times, 19 January, 2017.
12. Priyanka Singh, CPEC A Misnomer: India must Rename It ". The Pioneer, 18 June, 2017.
13. ‘‘कश्मीर संघर्ष: भारत-पाकिस्तान-चीन उलझन’’ डॉ नेताजी अभिनंदन, वर्ल्ड फोकस अंक 95 फरवरी 2020.

© Eureka Journals 2021. All Rights Reserved.